प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद– उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0/ 3063-3141 /2025–26 दिनांक 09-5-2025

विषयः– 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में है।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया की कार्यवाही शासनादेश संख्या–2056/68–4–2018 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिक संख्या–6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31277 एवं द्वितीय चरण में 36590 तथा शासनादेश संख्या–456/68 –5–2021–17/2020 दिनांक 17.05.2021 के अनुपालन में तृतीय चरण में 6696 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही तथा 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत अभिलेखीय विसंगति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1656/68–5–2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या–1657/68–5–2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या–53/68–5–2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 शासनादेश संख्या–54/68–5– 2021 दिनांक 16 जनवरी, 2021, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक महानिदेशक /व0वि0–स्कूल शिक्षा/शिक्षक भर्ती/8871/2020–21 दिनांक 18.01.2021, शासनादेश संख्या–80/68–5–2021 दिनांक 05 मार्च, 2020 के अनुपालन में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 अद्यतन संशोधित एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर जनपदीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–4127/2020 देवेन्द्र सिंह व 07 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 09.06.2022 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेशित किया गया–

This petition has been filed for a direction upon the respondents to proceed with the recruitment of Assistant Teachers for Junior Basic Schools run by the Board of Basic Education pursuant to Government Order dated 16.5.2020 strictly in consonance with Clause 1(IV) of the guidelines originally notified by the Board of Basic Education for such purpose. A further prayer is made to direct the respondents not to consider persons who are ineligible on the last date of making of application for recruitment etc.

Sri Arun Kumar, learned counsel appearing for the respondent Board has placed before the Court written instructions of the Deputy Secretary on behalf of the Board as per which the last date of making online application i.e. 22.12.2018 has been treated as the date for considering eligibility of the applicants concerned.

In view of the specific stand taken by the respondents, this Court finds that no further grievance survives for the petitioner. Writ petition is, accordingly, consigned to records while noticing the abovenoted stand of the respondents.

माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–9826/2021 अन्जलि सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 05.10.2021को निम्नवत् निर्णय पारित किया गया :–

Law is settled that eligibility of a candidate for appointment is to be seen with reference to the last date fixed for making of application. On the last date of making application i.e. 22.12.2018, petitioner was not possessing qualification of BTC. Merely because she has subsequently cleared the back paper would not mean that her eligibility from a retrospective date would stand revived. No exception can be taken if her claim is denied for such reasons.

Dismissed, accordingly.

माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–849/2021 प्रीती जाटव व 6 अन्य तथा सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को निम्नवत् निर्णय पारित किया गया है :–

15. It is the case of petitioners that appointment have been given to some candidates despite they were not qualified by last date of submission of form, however, the Court is of opinion that there is no concept of negative equality and for that few paragraphs of a recent judgment passed by Supreme Court in R. Muthukumar and Others Vs. Chairman and Managing Director TANGEDCO and Others , 2022 OnLine SC 151, would be relevant which are reproduced hereinafter :-

"28. A principle, axiomatic in this country's constitutional lore is that there is no negative equality. In other words, if there has been a benefit or advantage conferred on one or a set of people, without legal basis or justification, that benefit cannot multiply, or be relied upon as a principle of parity or equality. In Basawaraj v. Special Land Acquisition Officer, (2013) 14 SCC 81, this court ruled that:

"8. It is a settled legal proposition that Article 14 of the Constitution is not meant to perpetuate illegality or fraud, even by extending the wrong decisions made in other cases. The said provision does not envisage negative equality but has only a positive aspect. Thus, if some other similarly situated persons have been granted some relief/benefit inadvertently or by mistake, such an order does not confer any legal right on others to get the same relief as well. If a wrong is committed in an earlier case, it cannot be perpetuated."

29. Other decisions have enunciated or applied this principle (Ref : Chandigarh Admn. v. Jagjit Singh, (1995) 1 SCC 745, Anand Buttons Ltd. v. State of Haryana, (2005) 9 SCC 164 K.K. Bhalla v. State of M.P.,(2006) 3 SCC 581; Fuljit Kaur v. State of Punjab, (2010) 11 SCC 455, and Chaman Lal v. State of Punjab, (2014) 15 SCC 715). Recently, in The State of Odisha v. Anup Kumar Senapati, 2019 SCC OnLine SC 1207 this court observed as follows:

"If an illegality and irregularity has been committed in favour of an individual or a group of individuals or a wrong order has been passed by a judicial forum, others cannot invoke the jurisdiction of the higher or superior court for repeating or multiplying the same irregularity or illegality or for passing a similarly wrong order. A wrong order/decision in favour of any particular party does not entitle any other party to claim benefits on the basis of the wrong decision."

16. In the aforesaid circumstances, since petitioners were neither qualified by last date of submission of form nor they are entitled for benefit of any negative equality and argument of arbitrariness on basis of negative equality is also rejected and judgment cited by petitioner would not be helpful to them, therefore, there is no ground to interfere with impugned orders or to direct respondents to give appointment to petitioners.

15. Accordingly, all writ petitions are dismissed.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से स्पष्ट है कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करते समय समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख रजिस्ट्रेशन/आवेदन की अन्तिम दिनांक 22.12.2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य है।

69000 रिक्त पदो के सापेक्ष भर्ती किये जाने हेतु अधिसूचना/विज्ञप्ति दिनांक 01.12.2018 को जारी की गयी थी जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक गोप0/स0अ0भ0प0–19/21740–46/2018–19 दिनांक 05.12.2018 एवं कार्यालय के पत्रांक गोप0/स0अ0भ0प0–19/25819–25/2018–19 दिनांक 20.12.2019 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अन्तिम तिथि 22.12.2018 निर्धारित थी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अन्तिम तिथि 22.12.2018 तक शैक्षिक अर्हता धारित/पूरित नहीं करते हैं से उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तत्काल उनके सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त चयन हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी, चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन के उपरान्त जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियो के कार्यकाल का वर्षवार विवरण एक सप्ताह में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/ 3063-3141 /2025–26 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा–5 अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।

९.५.२५

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।